[Shri K. A. Rajan]

To tide over the crisis the Kerala State Government has requested the Government of India on 10-5-82 to sanction a loan amount of Rs. 24 crores to the State Government.

In the light of the above situation I urge upon the Central Government to take immediate steps in granting the loan and save the industry and one lakh of workers from utter distress.

(xi) NEED TO CONSTRUCT KICHAU DAM IN UTTAR PRADESH.

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : मैं उत्तर भारत की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना जिसे जमुना परियोजना के नाम से जाना जाता है की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा । जमुना जल विद्युत परियोजना को बने एक लम्बी अवधि होने को है । समुचित जल के अभाव के कारण अपनी क्षमताभर इस परियोजना से अभी तक कभी भी विद्युत उत्पादन नहीं हो सका ।

समुचित मात्रा में इस परियोजना के लिए जल उपलब्ध हो, इसके लिए किछाऊ नाम के एक बांध के निर्माण का विचार किया गया था जिससे इस योजना के लिए लगभग 1230 मिलियन क्यूबिक मीटर जल भण्डारण की व्यवस्था हो सके ।

उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने किछाऊ बांध परियोजना पर एक रिपोर्ट फरवरी, 1978 में केन्द्र सरकार को भेजी थी । केन्द्र ने इसकी जांच विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा करवाया है । तकनीशियनों तथा जांच अधिकारियों की राय में यमुना परियोजना से अपनी क्षमता भर विद्युत तभी उत्पादित हो सकती है जब किछाऊ बांध बनाकर जल भण्डारण की व्यवस्था हो । यह योजना मात्र इसलिए खटाई में पड़ी है क्योंकि योजान से संबंधित तटवर्ती राज्य हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में युमुना के जल के बटवारे के विवाद का निर्णय संबंधित राज्य बैठ कर नहीं कर पा रहे हैं । जनहित को ध्यान में रखते हुए केन्द्र का हस्तक्षेप वांछनीय हैं । मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा देश में बिजली के संकट को देखत हुए पन बिजली उत्पादन की इस महत्वपूर्ण योजना से क्षमता भर विद्युत उत्पादन के लिए किछाऊ बांध बनवाए जाने हेतु सभी राज्यों से बात करें और ऐसी व्यवस्था या उपाये करें जिससे किछाऊ बांध बनाया जा सके ।

(xii) NEED TO DECREASE RAILWAY FREIGHT CHARGES FOR TRANSPORTATION OF FRUITS.

श्री रसीद मसूद (सहारनपुर) : मैं रूल नं0 377 के तहत सरकार का ध्यान भुसावल में हो रही केले की खस्ताहाली की तरफ दिलाना चाहता हूं । सरकार ने 1982 में रेल भाड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से रेल के जरिए किसान की पैदा की हुई चीजों की कीमत भी बढ़ रही है और इस कदर भाड़ा देकर किसान अपनी पैदा की हुई चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी महसूस करता है । और खासतौर पर उन चीजों को जो ज्यादा दिन रखी नहीं जा उकतीं । मसलन, केला, आम और दीगर भी । रेल के महकमे में यह किराया रेलवे टेरिफ एन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश पर बढ़ाया है । मगर ऐसा दिखाई देता है कि इस कमेटी में तमाम हकायक पर गौर किए वगैर ऐसा कर दिया ।